भारत संघ

बनाम

एम. एस. मोहम्मद रॉथर

16 अगस्त, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जेजे.]

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980:

पेंशन के लिए दावा– रिट याचिका में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने भारत संघ को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया– अपील में खंड पीठ ने भारत संघ को याचिकाकर्ता को 9.9.1989 से पेंशन अनुदत करने का निर्देश दिया– अभिनिर्धारित कियाः एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया मार्ग सही था क्योंकि मामले में तथ्यों की आवश्यक जांच की जरुरत थी– यह राज्य और भारत संघ का कर्तव्य है कि वे इस विषय पर सभी सामग्री पर विचार करें और क्या यह मामला योजना के तहत पेंशन अनुदत करने योग्य है– न्यायालय कार्यकारी या विधायी क्षेत्र में

अतिक्रमण नहीं कर सकता है और तथ्यों की जांच की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता है– इसके पास वेंसबरी सिद्धांतों पर कार्यकारी आदेश का पुनर्विलोकन करने की केवल न्यायिक शक्ति है, लेकिन यह स्वयं के लिए कार्यपालिका की शक्ति को हड़प नहीं सकता है– न्यायालय को ऐसे मामलों में न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए– उच्च न्यायालय की खंड पीठ का आदेश रद्द किया जाता है– न्यायिक पुनर्विलोकन– न्यायिक संयम।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2002 की सिविल अपील संख्या 7336।

2001 की रिट अपील संख्या 2488 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 29.06.2001 से।

परमजीत सिंह पटवालिया, अमनप्रीत सिंह राही, वी. मोहना और सुषमा सुरी अपीलार्थी की ओर से।

संजय पारिख, ए. एन. सिंह और जितिन साहनी प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का आदेश दिया गया।

आदेश

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

यह अपील केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा केरल उच्च् न्यायालय की खंडपीठ ने भारत संघ को याचिकाकर्ता (यहां प्रत्यर्थी) को 09.09.1989 से स्वतंत्रता सम्मान सैनिक पेंशन (संक्षेप के लिए एसएसएस पेंशन) अनुदत्त किये जाने का निर्देश दिया हैः जैसा कि उसने अपनी मूल याचिका में दावा किया है और राशि का भुगतान दो महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। इस आदेश से व्यथित होकर, वतर्मान अपील भारत संघ द्वारा दायर की गई है।

हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

खंडपीठ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता को एस.एस.एस. पेंशन अनुदत्त करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए भारत संघ को निर्देश दिया

था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने ईएक्सएच॰ पी-6 और ईएक्सएच॰ पी-8 (पेंशन के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए भारत संघ द्वारा पारित आदेश) को रद्द कर दिया और प्रत्यर्थी को एसएसएस पेंशन देने के लिए उसकी प्रार्थना पर विचार करने का एक आवश्यक अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए भारत संघ को वापस भेज दिया। इस आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता द्वारा मामले को खंड पीठ के समक्ष उठाया गया, जिस पर खंड पीठ ने आक्षेपित आदेश पारित किया गया। इस कारण भारत संघ की वर्तमान अपील।

हमने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया रास्ता सही था और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के अनुदान के प्रश्न पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामला भारत संघ को वापस भेजा जाना चाहिए था। इसमें तथ्यों की आवश्यक जांच की जरूरत थी कि क्या पदधारी एसएसएस पेंशन का हकदार था या नहीं। अदालतें कार्यकारी या विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं और तथ्यों की जांच की भूमिका नहीं निभा सकती है। यह राज्य और भारत संघ का

कर्तव्य है कि वह इस विषय पर सभी सामग्री पर विचार करें और विचार करें कि क्या यह एसएसएस पेंशन योजना, 1980 के अनुसार पेंशन देने योग्य मामला है। न्यायालय के पास वेंसबरी सिद्धांतों पर उस कार्यकारी आदेश का पुनर्विलोकन करने की केवल न्यायिक शक्ति है, लेकिन वह कार्यपालिका की शक्ति को अपने लिए हड़प नहीं सकता है। यदि भारत संघ द्वारा पारित आदेश वेंसबरी सिद्धांतों पर न्यायोचित नहीं है तो न्यायालय इसे केवल रद्द कर सकता है और मामले को नए निर्णय के लिए कार्यपालिका को वापस भेज सकता है, लेकिन न्यायालय भारत संघ की शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता है। न्यायालय को ऐसे मामलों में न्यायिक संयम बरतना चाहिए। संविधान के तहत शक्तियों का व्यापक विभाजन है, और राज्य के एक अंग को सामान्य रूप से दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मोंटेस्क्यू का सिद्धांत भारत में भी व्यापक रूप से लागू होता है।

तदनुसार, हम खंड पीठ के आदेश को अपास्त करते हैं और भारत संघ को मामला वापस भेजा जाता है। भारत संघ विचार करेगा और आज से अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर विधिअनुसार एक उचित आदेश पारित करेगा।

हमें सूचित किया गया है कि इसमें प्रत्यर्थी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यदि यह पाया जाता है कि वह पेंशन का हकदार था तो उसके सभी बकाया की गणना की जानी चाहिए और उसके विधिक उत्तराधिकारियों को दी जावे।

तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

आर. पी.

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भानुप्रिया जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।